शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 12 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 16 – 23 मार्च 2026 मूल्य पांच रूपये

हिमाचल का 54,928 करोड़ रूपये का बजट

ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026 – 27 का 54,928 करोड़ रुपये का बजट राज्य की आर्थिक दिशा, सामाजिक प्राथमिकताओं और विकास की रणनीति का व्यापक दस्तावेज है। यह बजट ऐसे समय में आया है जब राज्य को राजस्व घाटे, सीमित संसाधनों और बढ़ती विकास आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना है। इसके बावजूद सरकार ने 8.3 प्रतिशत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर, 2,83,626 रुपये की प्रतिव्यक्ति आय और 2.54 लाख करोड़ रुपये के सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य निर्धारित कर यह संकेत दिया है कि विकास की गति बनाए रखने की ठोस कोशिश की जा रही है।

इस बजट का सबसे बड़ा फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका सुदृढ़ीकरण पर है। डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियों की संख्या को दोगुना कर 2,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दूध उत्पादकों को मिलने वाला प्रोत्साहन 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर किया गया है, जिससे सीधे हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। पशुपालक समुदायों गद्दी, गुज्जर, किन्नौरा आदि के 40,000 से अधिक परिवारों के लिए 300 करोड़ रुपये की विशेष योजना शुरू की जाएगी। ऊन के लिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है, जो पशुपालकों की आय बढ़ाने में सहायक होगा।

कृषि क्षेत्र में भी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है, जबकि मक्का 40 से 50 रुपये, जौ 60 से 80 रुपये और हल्दी 90 से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम की गई है। पहली बार अदरक को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के MSP में शामिल करना किसानों के लिए बड़ी राहत है। 'बीज गांव' योजना के तहत किसानों को प्रति बीघा 5,000 रुपये की सब्सिडी और प्रत्येक गांव को 2 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा, जिससे पारंपरिक बीजों का संरक्षण और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

बागवानी और वन क्षेत्र में सरकार ने 8,000 हेक्टेयर में पौधरोपण और 4,000 हेक्टेयर में सामुदायिक वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है। 1,100 सामुदायिक समूहों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। 'मिशन 32 प्रतिशत' के तहत वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र को 32 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, 50 नए ईको – टूरिज्म स्थलों का विकास और 50 वन विश्राम गृहों की ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ – साथ पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती देगी।

सामाजिक कल्याण और महिला – बाल विकास के क्षेत्र में इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,700 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह किया गया है। 'शुभ विवाह योजना' के तहत पात्र महिलाओं को 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपये तक का सब्सिडीयुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, पुनर्वास के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी।

शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। 150 स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जबकि 150 अन्य स्कूलों को भी समान स्तर पर उन्नत किया जाएगा। राजीव गांधी डे – बोर्डिंग स्कूलों के लिए 99 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बच्चों के पोषण के लिए 17 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। उच्च शिक्षा में 389 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती और नए व्यावसायिक पाठयक्रम शुरू किए जाएंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट का आकार और दृष्टिकोण दोनों व्यापक हैं। नाहन मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये, चंबा मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए 194 करोड़ रुपये और हमीरपुर में नए डेंटल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। टांडा, हमीरपुर और शिमला में आधुनिक कैंसर उपचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 18 डे – केयर कैंसर सेंटर और 4 टर्शियरी केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, 150 स्टाफ नर्स, 500 रोगी मित्र, 40 फार्मेसी अधिकारी और 30 रेडियोग्राफर सहित 1,000 से अधिक पद भरे जाएंगे।

ऊर्जा क्षेत्र में 450 करोड़ रुपये की लागत से बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। 5 से 11 मेगावाट क्षमता की छः सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। पांवटा साहिब में 124 करोड़ रुपये और कांगड़ा में 221 करोड़ रुपये की लागत से पंचायत स्तर पर सोलर परियोजनाओं से होने वाली आय का 30 प्रतिशत पंचायत और 20 प्रतिशत कमजोर वर्गो के कल्याण पर खर्च किया जाएगा।

पर्यटन क्षेत्र में 345 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विकास कार्यो पर खर्च की जाएगी। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 3,349 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, कई नए हेलीपोर्ट्स का निर्माण और हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

जल आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में लगभग 2,000 करोड़ रुपये की व्यापक योजना तैयार की गई है। 500 जल योजनाओं में शोधन संयंत्र लगाए जाएंगे और 200 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइन बदली जाएगी। शिमला में 10,000 घरों को 24x7 जल आपूर्ति देने का लक्ष्य रखा गया है।

सड़क और परिवहन क्षेत्र में 500 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 950 किलोमीटर सड़कों की टारिंग, 1,500 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण और 47 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2,244 करोड़ रुपये की लागत से 1,538 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति दी गई है।

ग्रामीण विकास के तहत 1 लाख गरीब परिवारों को 'मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना' के अंतर्गत 300 यूनिट मुफ्त बिजली और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह की सहायता भी दी जाएगी।

आईटी और नवाचार क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने, डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने और ई – गवर्नेंस को लागू करने पर जोर दिया गया है। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता और दक्षता में सुधार होगा।

कर्मचारी कल्याण के तहत एनएचएम कर्मचारियों को औसतन 14,000 रुपये की वेतन वृद्धि दी जाएगी। डॉक्टरों का वेतन 33,660 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये किया गया है। दैनिक वेतनभोगियों का वेतन 450 रुपये प्रतिदिन और आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 13,750 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री के वेतन में 50 प्रतिशत, मंत्रियों के वेतन में 30 प्रतिशत और विधायकों के वेतन में 20 प्रतिशत की अस्थायी कटौती की गई है। यह कदम दर्शाता है कि सरकार आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए सख्त निर्णय लेने को तैयार है।

कुल मिलाकर यह बजट आंकड़ों के माध्यम से स्पष्ट करता है कि सरकार ने ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन और अवसंरचना पर व्यापक निवेश की योजना बनाई है। हालांकि, इन योजनाओं की वास्तविक सफलता उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। यदि सरकार इन घोषणाओं को धरातल पर उतारने में सफल रहती है, तो यह बजट हिमाचल प्रदेश के लिए दीर्घकालिक और समावेशी विकास की मजबूत नींव साबित हो सकता है।

'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' अभियान से मजबूत हो रही राष्ट्रीय एकता:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि एक भारत, श्रेष्ठ भारत अभियान राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को सुदृढ़ कर रहा है। उन्होंने यह बात लोक भवन में ओडिशा से आये पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट के दौरान कही।

प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो के तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय इस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधिमंडल शिमला, कुल्लू और मनाली सहित विभिन्न स्थानों का दौरा करेगा। पत्रकारों ने राज्यपाल के साथ अपने अनुभव साझा किए और प्रदेश की समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं पर चर्चा की।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित इस कार्यक्रम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि भारत विविध भाषाओं और बोलियों का देश है, जहां 'विविधता में एकता' इसकी सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने अपने लद्दाख कार्यकाल का उल्लेख करते हुए बताया कि वहां भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया।

उन्होंने कहा कि जहां औपनिवेशिक काल में देश को विभाजित करने के प्रयास हुए, वहीं ऐसे कार्यक्रम आज राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रहे हैं।

राज्यपाल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए स्थानीय उत्पादों के प्रचार-प्रसार, औषधीय पौधों की खेती, नशा मुक्ति और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पर्यटन को शीतकालीन खेलों से जोड़ने और युवाओं के लिए कौशल विकास के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया।

औद्योगिक विकास पर उन्होंने कहा कि उद्योगों को मजबूत बनाए रखना जरूरी है और समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद के माध्यम से राज्य के विकास को गति दी जा सकती है।

इससे पूर्व, प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो के सहायक निदेशक संजीव शर्मा ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन का भी दौरा किया और इसके संरक्षण की सराहना की। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा भी उपस्थित रहे।

शहीद दिवस पर राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर लोक भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा दो मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया।

राज्यपाल ने कहा कि शहीदों का जीवन युवाओं के लिए साहस, प्रतिबद्धता और निःस्वार्थ राष्ट्र सेवा की प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि इन महान क्रांतिकारियों की देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और सभी को इन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इन शहीदों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर स्वतंत्र भारत की नींव रखी, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। शहीद भगत सिंह से अपने व्यक्तिगत जुड़ाव का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने उनके परिजनों के साथ सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया है और अपने बचपन में हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है।

राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब प्रत्येक नागरिक राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएगा। उन्होंने युवाओं से आहवान किया कि वे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से प्रेरणा लेकर ईमानदारी, अनुशासन और त्याग की भावना के साथ राष्ट्र सेवा में योगदान दें।

इस अवसर पर राज्यपाल ने लोक भवन के कर्मचारियों के साथ संवाद भी किया और उन्हें परंपराओं का सम्मान करते हुए निष्ठा से कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए नियमित संवाद का आश्वासन भी दिया।

राज्यपाल से एचपीयू और नौणी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की मुलाकात

शिमला/शैल। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से लोक भवन में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. महावीर सिंह और डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने शिष्टाचार भेंट की।

इस दौरान कुलपतियों ने अपने-अपने विश्वविद्यालयों में चल रही शोध और विकास गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने, विद्यार्थियों में नवाचार को बढ़ावा देने और कौशल आधारित शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों से राज्यपाल को अवगत करवाया।

बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार पर भी विस्तार से चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा को वैश्विक स्तर के अनुरूप बनाना जरूरी है, ताकि विद्यार्थी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। उन्होंने युवाओं के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए जीवन मूल्यों, कौशल विकास और शोध आधारित शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय देश के भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं और विद्यार्थियों को जिम्मेदार, कुशल व जागरूक नागरिक बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। साथ ही, शिक्षा में नई तकनीकों और आधुनिक पद्धतियों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया।

इस अवसर पर यूएई और भारत में 'स्पेशल एन्वाय' कनिका चौधरी ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। बैठक में भारत और यूएई के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई।

राज्यपाल ने दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों की सराहना करते हुए हिमाचल प्रदेश में पर्यटन, बागवानी और शिक्षा के क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को उजागर किया। उन्होंने ज्ञान के आदान-प्रदान, नवाचार और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया।

इस दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के कुलपति प्रो. एस.पी. बंसल भी उपस्थित रहे।

मातृभाषा पर गर्व और युवाओं की भूमिका से ही बनेगा 'विकसित भारत 2047': राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की भाषा उसकी आत्मा और पहचान होती है, इसलिए युवाओं को अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए। वह नागपुर स्थित महर्षि व्यास सभागार में आयोजित भारतीय युवा संसद के राष्ट्रीय सत्र को संबोधित कर रहे थे।

यह सत्र भारतीय युवा संसद-मीडिया फाउंडेशन और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जिसमें देशभर से लगभग 600 युवाओं ने भाग लेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

राज्यपाल ने कहा कि भाषाएं केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, स्मृति और पहचान की वाहक होती हैं। उन्होंने युवाओं में मातृभाषा के प्रति बढ़ती झिझक पर चिंता जताते हुए कहा कि अंग्रेजी सीखना आवश्यक है, लेकिन अपनी भाषा की कीमत पर नहीं।

उन्होंने नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंचों-जैसे संयुक्त राष्ट्र और जी सम्मेलनों पर हिंदी के प्रयोग को सांस्कृतिक आत्मविश्वास का उदाहरण बताया। साथ ही 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' में हिंदी में दिए गए संबोधन का भी उल्लेख किया।

राज्यपाल ने 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि देश का भविष्य युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आहवान किया।

उन्होंने 'पंच परिवर्तन' स्वबोध, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक कर्तव्य को जीवन में अपनाने की भी अपील की।

इससे पूर्व राज्यपाल ने नागपुर स्थित स्मृति भूमि में केशव बलिराम हेडगेवार और माधव सदाशिव गोलवलकर को श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

नव नियुक्त कृषि विकास अधिकारियों का वैज्ञानिकों से संवाद

केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में 37 अधिकारियों ने लिया हिस्सा

शिमला/शैल। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में नव नियुक्त कृषि विकास अधिकारियों (एडीओ) के लिए संवाद और अनुभव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों को आधुनिक कृषि तकनीकों और अनुसंधान से जोड़ना था।

राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (समेती) के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में 37 नव नियुक्त अधिकारियों ने भाग लिया। ये अधिकारी अपने प्रारंभिक प्रशिक्षण के तहत शामिल हुए और जल्द ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात किए जाएंगे।

संस्थान के निदेशक डॉ. ब्रजेश सिंह ने इस अवसर पर कहा कि संस्थान बेहतर आलू किस्मों के विकास और आधुनिक खेती तकनीकों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से किसानों के हित में वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करने का आहवान किया।

समेती के निदेशक डॉ.एस.के. गुप्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों को उन्नत तकनीकों की व्यावहारिक जानकारी देना है, ताकि वे किसानों तक सही जानकारी पहुंचा सकें।

कार्यक्रम के दौरान आयोजित तकनीकी सत्र में वैज्ञानिकों ने बीज उत्पादन, फसल प्रबंधन, रोग नियंत्रण और भंडारण तकनीकों पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही, अनुसंधान संस्थानों से किसानों तक तकनीक के प्रभावी हस्तांतरण पर भी जोर दिया गया।

अधिकारियों ने इस पहल को उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे उन्हें जमीनी चुनौतियों को समझने और किसानों को बेहतर परामर्श देने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम के अंत में उप-प्राचार्य डॉ. सुनीता ठाकुर ने संस्थान का आभार जताया, प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अनिल चौधरी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल से मुख्य सचिव और डीजीपी की मुलाकात, प्रशासन व कानून-व्यवस्था पर चर्चा

शिमला/शैल। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से लोक भवन में मुख्य सचिव संजय गुप्ता और पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने शिष्टाचार भेंट की।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राज्यपाल को प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति, विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और सेवा वितरण प्रणाली में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही, जन शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निवारण को लेकर उठाए जा रहे कदमों पर भी प्रकाश डाला।

पुलिस महानिदेशक ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए बताया कि जन सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस बल के आधुनिकीकरण और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने की पहलों का भी उल्लेख किया।

राज्यपाल ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मजबूत कानून-व्यवस्था, सतर्क प्रशासन और जनहितैषी दृष्टिकोण राज्य के समग्र विकास, शांति और जनकल्याण के लिए आवश्यक हैं।

सीआईआई मंच से हिमाचल में निवेश का न्योता

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योगपतियों को हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि सरकार पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और सूचना

प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्रों को विशेष रूप से बढ़ावा दे रही है।

शिमला में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हरित और पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र में करीब 3,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हेलीपोर्ट बनाए जा रहे हैं और हेली-टैक्सी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार भी जारी है, जिससे आने-जाने में आसानी होगी।

उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि किसी का भी उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। यदि कोई समस्या आती है तो निवेशक सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम को और आसान बनाने की बात कही, ताकि सभी मंजूरियां एक ही जगह मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्दी और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। बद्दी में अंडरग्राउंड डक्ट्स बनाए जाएंगे, बिजली की समस्याएं दूर की जाएंगी और ऊना के हरोली में बल्क ड्रग पार्क विकसित किया जा रहा है। बद्दी तक रेलवे लाइन बढ़ाने में भी राज्य सरकार 50 प्रतिशत खर्च उठा रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश को 'उत्तर भारत की प्राणवायु' और 'जल का भंडार' कहा जाता है, लेकिन इसके अनुसार आर्थिक लाभ नहीं मिला। केंद्र से मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को बंद किए जाने पर उन्होंने चिंता जताई और इसे फिर से शुरू करने की मांग की।

इस मौके पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की दिशा में काम कर रही है और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सम्मेलन में कई उद्योगपति और सीआईआई के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

चुनौतियों के बावजूद शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में कटौती नहीं:मुख्यमंत्री

प्रधानाचार्य सम्मेलन में उच्च शिक्षा सुधार न्यू एज कोर्स और भाषा कार्यक्रमों पर जोर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के बजट में कोई कटौती नहीं करेगी। वह उच्च शिक्षा सुधारों पर आयोजित एक दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और दूरदराज क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षक इस दिशा में अहम भूमिका निभाते हैं।

उच्च शिक्षा में सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि विज्ञान, वाणिज्य और ललित कला जैसे विषयों के लिए विशेष महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। हमीरपुर में 50 बीघा भूमि पर विज्ञान कॉलेज स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी विशेष कॉलेज स्थापित करने की योजना है।

उन्होंने कहा कि सहायक प्राध्यापकों और जूनियर सहायक प्राध्यापकों के 400-400 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। कॉलेजों में न्यू एज पाठयक्रम और अतिरिक्त भाषा कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ सके। साथ ही, कॉलेजों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रैंकिंग प्रणाली भी लागू की गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग का पुनर्गठन कर स्कूल शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशालय स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के शिक्षक सक्षम हैं और ये सुधार उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सीबीएसई स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ने का भी उन्होंने उल्लेख किया।

स्वास्थ्य क्षेत्र पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक एमआरआई मशीनें स्थापित की गई हैं और चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू की जा रही है।

उन्होंने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का जिक्र करते हुए कहा कि यह कोई राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से लिया गया निर्णय है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद किए जाने और 1600 करोड़ रुपये की सहायता न मिलने से राज्य पर वित्तीय दबाव बढ़ा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालयों की आंतरिक रैंकिंग जारी की। समग्र रैंकिंग में हमीरपुर कॉलेज पहले, संजौली कॉलेज दूसरे और राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला तीसरे स्थान पर रहा। विभिन्न श्रेणियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कॉलेजों को सम्मानित किया गया और प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई।

कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिक्षा सचिव राकेश कंवर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और प्रदेश भर के कॉलेजों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।

जल जीवन मिशन 2.0 पर एमओयू साइन पहाड़ी राज्यों के लिए अलग मापदंड की मांग

मुख्यमंत्री ने केंद्र से 1,227 करोड़ जारी करने का किया आग्रह

शिमला/शैल। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 के तहत एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप-मुख्यमंत्री

मुकेश अग्निहोत्री शिमला से वर्चुअली जुड़े, जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रीसी. आर. पाटिल ने भी वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

समझौते पर राज्य की ओर से जल शक्ति विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन और केंद्र की ओर से संयुक्त सचिव स्वाति नायक ने हस्ताक्षर किए। जेजेएम 2.0 को दिसम्बर 2028 तक लागू किया जाएगा, जिसमें पेयजल अधोसंरचना के पुनर्निर्माण और ग्रामीण जलापूर्ति प्रणाली में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में परियोजनाओं की निर्माण लागत अधिक होती है। ऐसे में समान मापदंड लागू करना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जलापूर्ति योजनाओं के प्रबंधन को बढ़ावा दे रही है।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से जेजेएम के तहत लंबित 1,227 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उनका भुगतान अभी तक लंबित है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में आधुनिक तकनीकों को अपनाया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके।

कैबिनेट रैंक का दर्जा वापस, प्रशासनिक प्रोटोकॉल होगा सुव्यवस्थित

बोर्ड, निगम और आयोगों के पदाधिकारियों पर लागू फैसला, भत्तों में 20% कटौती अस्थायी

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने प्रशासनिक प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्राधिकरणों को दिए गए 'कैबिनेट रैंक' के दर्जे को वापस लेने का निर्णय लिया है। यह जानकारी सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने दी।

प्रवक्ता के अनुसार, यह निर्णय बोर्ड, निगम और आयोगों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, प्रधान सलाहकार और राजनीतिक सलाहकार जैसे पदों पर लागू होगा। निर्णय के साथ ही इन पदों को 'कैबिनेट रैंक' से संबंधित सभी सुविधाएं और प्रावधान तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए गए हैं।

सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और स्पष्ट बनाने की दिशा में उठाया गया है, ताकि पदानुक्रम और प्रोटोकॉल में अनावश्यक जटिलताओं को कम किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, संबंधित पदाधिकारियों के वेतन और मासिक भत्तों का 20 प्रतिशत हिस्सा 30 सितम्बर 2026 तक अस्थायी रूप से स्थगित रखने का भी निर्णय लिया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि निर्णय का त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

एसडीआरएफ की राष्ट्रीय सीएसएसआर प्रतियोगिता में जीत, हिमाचल के लिए गर्व का क्षण: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की राष्ट्रीय स्तर पर लगातार दूसरी जीत को हिमाचल के लिए गर्व

का विषय बताया है। रविवार को शिमला स्थित ओक ओवर में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने विजेता टीम को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए और उनके कार्य की सराहना की।

एसडीआरएफ टीम ने हाल ही में राष्ट्रीय कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू (CSSR) प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस दौरान टीम ने मात्र 41 मिनट में चुनौती पूरी कर अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। प्रतियोगिता में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 30 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें हिमाचल पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल करना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने हाल के वर्षों में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि एसडीआरएफ, होम गार्ड्स, अग्निशमन सेवाओं और सिविल डिफेंस ने राहत एवं बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने होम गार्ड वॉलंटियर मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली राज्यभर में स्वयंसेवकों के बेहतर समन्वय और दक्षता को बढ़ाएगी। साथ ही फायर सेफ्टी कोड 2026 की समीक्षा कर आपदा प्रबंधन तंत्र को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

यह प्रतियोगिता 9 से 11 मार्च 2026 के बीच गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की 8वीं बटालियन परिसर में आयोजित हुई थी।

समारोह में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

अनाडेल आर्मी हेरिटेज म्यूजियम में जीर्णोद्धार के बाद श्रद्धांजलि स्थल जनता को समर्पित

शिमला/शैल। आर्मी ट्रेनिंग कमांड (आरट्रैक) के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन- चीफ देवेंद्र शर्मा ने आर्मी हेरिटेज म्यूजियम में जीर्णोद्धार कार्यों के उपरांत श्रद्धांजलि स्थल को जनता को समर्पित किया।

इस अवसर पर उन्होंने 52 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। यह विशाल तिरंगा राष्ट्र की एकता, अखण्डता और गौरव का प्रतीक है। आर्मी हेरिटेज म्यूजियम शिमला के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां वर्षभर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं।

समारोह में आरट्रैक के अधिकारियों, जवानों, स्टेशन यूनिट्स, पूर्व सैनिकों तथा एनसीसी कैडेट्स ने भाग लेकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर स्थापित स्मारक और राष्ट्रीय ध्वज भारतीय सेना की शहीदों के प्रति सम्मान, वीरता, बलिदान और देशभक्ति की समृद्ध परंपरा को संरक्षित रखने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

स्वास्थ्य ही असली धन है, न कि सोने – चाँदी के टुकड़े।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

आर्थिक संकट, राजनीतिक विफलता और वित्तीय अनुशासन पर गंभीर प्रश्न

हिमाचल प्रदेश का बजट 2026-27 केवल एक वित्तीय दस्तावेज़ नहीं, बल्कि वर्तमान शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली, प्राथमिकताओं और प्रशासनिक क्षमता का आईना बनकर सामने आया है। प्रस्तुत बजट में जहां एक ओर विकास और कल्याण की कई घोषणाएं की गई हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर गहरे सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। यह बजट कई मायनों में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के बजाये आर्थिक असंतुलन, बढ़ते कर्ज और राजकोषीय दबाव की कहानी अधिक प्रतीत होता है।

राज्य का कुल बजट आकार 54,928 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद लगभग 2.54 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। 8.3 प्रतिशत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय 2.83 लाख रुपये बताई गई है, जो कागज़ों पर सकारात्मक संकेत देती है। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छिपी वास्तविकता यह है कि राज्य की वित्तीय स्थिति लगातार दबाव में है। बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा, कर्ज पर निर्भरता और राजस्व संसाधनों की सीमित क्षमता इस बजट की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी बनकर सामने आई है।

सबसे गंभीर चिंता का विषय यह है कि राज्य सरकार कर्ज लेकर पुराने कर्ज चुकाने की स्थिति में पहुंचती दिख रही है। यह स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक खतरे का संकेत होती है। वित्तीय प्रबंधन का यह मॉडल न केवल अस्थिर है, बल्कि भविष्य में राज्य को गहरे आर्थिक संकट की ओर धकेल सकता है। यदि यही प्रवृत्ति जारी रहती है, तो हिमाचल प्रदेश वित्तीय अनुशासन की सीमाओं को पार करते हुए एक गंभीर संकट की ओर बढ़ सकता है।

इस बजट में 'फ्रीबीज' या लोकलुभावन योजनाओं पर अत्यधिक जोर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुफ्त बिजली, मानदेय वृद्धि, सामाजिक योजनाओं का विस्तार-ये सभी कदम राजनीतिक दृष्टि से आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए ठोस राजस्व स्रोतों का अभाव राज्य की वित्तीय स्थिति को और कमजोर कर सकता है। अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को जोखिम में डालना एक चिंताजनक प्रवृत्ति है।

राज्य सरकार की प्रशासनिक क्षमता और वित्तीय प्रबंधन पर भी इस बजट ने प्रश्नचिह्न लगा दिया है। अनियोजित व्यय, प्राथमिकताओं में असंतुलन और दीर्घकालिक रणनीति का अभाव यह दर्शाता है कि शासन प्रणाली में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। केवल घोषणाओं और योजनाओं से विकास संभव नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य है।

हालांकि, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी राज्य को 'विफल राज्य' घोषित करना एक अत्यधिक कठोर और राजनीतिक रूप से संवेदनशील निष्कर्ष होता है। हिमाचल प्रदेश अभी भी कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है-शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास और मानव विकास सूचकांक के मामले में राज्य की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत रही है। इसलिए स्थिति को पूरी तरह निराशाजनक मानना उचित नहीं होगा, बल्कि इसे एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए।

आगे का रास्ता स्पष्ट है-राज्य को वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देनी होगी। गैर-जरूरी खर्चों में कटौती, राजस्व बढ़ाने के उपाय, निवेश को प्रोत्साहन और प्रशासनिक सुधार ही इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं। साथ ही, सरकार को लोकलुभावन नीतियों के बजाय टिकाऊ और दीर्घकालिक विकास मॉडल अपनाने की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश का बजट 2026-27 एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है -यह या तो सुधार और पुनर्गठन की दिशा में कदम बन सकता है, या फिर वित्तीय अस्थिरता की ओर बढ़ने का संकेत। निर्णय और दिशा दोनों ही राज्य सरकार के हाथ में हैं। यदि समय रहते ठोस और व्यावहारिक कदम उठाए जाते हैं, तो संकट को अवसर में बदला जा सकता है अन्यथा यह बजट आने वाले समय में एक गंभीर आर्थिक चुनौती का आधार बन सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय:आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में ग्राम सभा सर्वोच्च, धर्मांतरण किसी रूप में स्वीकार नहीं

गौतम चौधरी

भारत की जनजातीय पहचान केवल सामाजिक ढांचे का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा है, जो प्रकृति, सामुदायिक जीवन और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है। इस बात पर एक बार फिर, भारत के माननीय सार्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगा दी है। हाल ही में दिग्भल टंडी बनाम छत्तीसगढ राज्य के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि ग्राम सभा का निर्णय सबसे उपर है और उसके साथ कोई छेड़-छाड़ नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने न केवल एक बहस छेड़ दी है, अपितु आने वाले समय के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। यह फैसला केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जनजातीय समाज के दशकों पुराने सांस्कृतिक संघर्षो की मान्यता को भी संपुष्ट करता है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने ग्राम सभाओं द्वारा ईसाई मिशनरियों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों को उचित ठहराते हुए यह स्पष्ट किया कि यह कदम दमनकारी नहीं, बल्कि एक निवारक उपाय है-जिसका उद्देश्य जनजातीय संस्कृति और सामाजिक अखंडता की रक्षा करना है। यह निर्णय पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) की भावना के अनुरूप है, जो ग्राम सभाओं को अपनी परंपराओं और संसाधनों की रक्षा का अधिकार देता है।

यह पहली बार नहीं है जब न्यायपालिका ने धर्मांतरण के प्रश्न पर सीमाएँ निर्धारित की है। वर्ष 1977 के ऐतिहासिक मामले रेव. स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि धर्म प्रचार का अधिकार धर्मांतरण का मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता है। वर्तमान निर्णय इसी संवैधानिक व्याख्या को आगे बढ़ाता है, विशेषकर तब जब धर्मांतरण के पीछे प्रलोभन, धोखे या सेवाओं के दुरुपयोग की आशंका हो।

इस संदर्भ में इतिहास की भी थोड़ी जानकारी जरूरी है। भगवान बिरसा मुंडा ने औपनिवेशिक काल में न केवल राजनीतिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया, बल्कि उन धार्मिक प्रभावों का भी विरोध किया जो आदिवासी संस्कृति को कमजोर कर रहे थे। उनका 'उलगुलान' केवल विद्रोह नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आहवान था। इसी तरह जतरा टाना भगत ने सामाजिक सुधार और धार्मिक शुद्धता के माध्यम से आदिवासी समाज को अपनी जड़ों की ओर लौटने का संदेश दिया।

स्वतंत्र भारत में बाबा कार्तिक उरांव ने संसद के भीतर और बाहर यह चेतावनी दी कि धर्मांतरण आदिवासियों को उनकी मूल पहचान से काट देता है। उनके अनुसार, यह केवल आस्था का परिवर्तन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विघटन की प्रक्रिया है। आधुनिक चिंतन में डॉ. रामदयाल मुंडा ने इस विमर्श को बौद्धिक आधार प्रदान किया। उन्होंने आदिवासी जीवन-दर्शन को प्रकृति के साथ संतुलन, सामूहिकता और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता पर आधारित बताया और बाहरी हस्तक्षेपों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. मुंडा बराबर कहते थे, ''जे नाची से बांची''- इसका अर्थ यह है कि जो अपनी संस्कृति में रमा रहेगा वही बचेगा।

हालांकि, यह विषय केवल एक पक्षीय नहीं है। एक ओर जहां आदिवासी अस्मिता की रक्षा आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता भी संविधान का मूल तत्व है। यही कारण है कि यह निर्णय एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है-जहाँ व्यक्ति के अधिकार और समुदाय के अधिकार, दोनों को ध्यान में रखा गया है।

फिर भी, यह आवश्यक है कि इस प्रकार के प्रतिबंधों का उपयोग मनमाने ढंग से न हो। ग्राम सभाओं की शक्तियाँ जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ संचालित हों, ताकि वे संरक्षण के नाम पर दमन का माध्यम न बनें। साथ ही, राज्य की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में ऐसी नीतियां बनाए, जो आदिवासी समाज को सशक्त करें, न कि उन्हें बाहरी निर्भरता की ओर धकेलें।

अंततः, यह स्पष्ट है कि जनजातीय विरासत का संरक्षण केवल एक सांस्कृतिक मुद्दा नहीं, बल्कि भारत की बहुलतावादी पहचान की रक्षा का प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है-जो यह संदेश देता है कि विकास और आधुनिकता के साथ-साथ सांस्कृतिक जड़ों की रक्षा भी उतनी ही अनिवार्य है।

कविता

स्मृति श्रीवास्तव

''इंकलाब लिख दिया जिसने अपने खून से...''

दहक उठी थी ज्वाला मन में
जब देश गुलामी में जकड़ा था
नन्हीं आंखों ने जलियांवाला का
वो खूनी मंजर पकड़ा था

मिट्टी को माथे से लगाकर
उसने कसम ये खाई थी
गोरी सत्ता को उखाड़ने की
उसने अलख जगाई थी

वह डरा नहीं फांसी के फंदों
से, न बेड़ियों की झंकार से
वो गूंज उठा था इंकलाब
बन, असेंबली की दीवार से

पिस्तौल नहीं, विचारों से उसने
क्रांति की लौ जलाई थी
सोए हुए उस भारतवर्ष में
नई चेतना फैलाई थी

न झुका कभी जुल्मों के आगे
न ही थमी कभी उसकी चाल
देशभक्ति के रंग में रंगा था
वो भारत का कर्मठ लाल

न ही उम्र की फिक्र थी उसको
न मौत का कोई ख़ौफ़ था
वतन की खातिर मर मिटने का
बस एक यही शौक था

भगत ने सुखदेव राजगुरु संग
जब फांसी का फंदा चूमा था
इंकलाब के नारों से तब
सारा भारत गूंजा था

वो छोटा सा निर्भीक बालक
भारत का अभिमान बना
जिसकी रगों में दौड़ता लहू
आज़ादी का गान बना

छोटी सी उम्र में ही भगत की
हस्ती ने रचा इतिहास नया
उसकी मौत शहादत थी जिसने
युवा रक्त को जगा दिया

उठो, हिंद के वीर जवानों !
उसके बलिदान को पहचानो
देशप्रेम ही धर्म है अपना
बस इस बात को तुम जानो !!!

जल का उत्सव, जन भागीदारी का संकल्प

सी आर पाटील
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री

प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व जल दिवस के अवसर पर मैं सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जल केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन की आधारशिला है।और इसका संरक्षण हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।

जल हमारे जीवन, पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थव्यवस्था की धुरी है। विश्व की लगभग 18 प्रतिशत जनसंख्या और पशुधन भारत में निवास करते हैं, जबकि हमारे पास वैश्विक मीठे जल संसाधनों का मात्र 4 प्रतिशत ही उपलब्ध है। शहरीकरण, बढ़ती मांग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बीच जल का प्रभावी प्रबंधन आज एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुका है।

इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना से जल से जुड़े विभिन्न विभागों का एकीकरण हुआ है, जिससे योजनाओं के बेहतर और समन्वित क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह दृष्टिकोण जल के पूरे चक्र को साथ लेकर चलता है। एक ओर संरक्षण और भूजल पुनर्भरण पर बल दिया जा रहा है, वहीं बांधों और जलाशयों के माध्यम से भंडारण क्षमता को मजबूत किया जा रहा है। नदी जोड़ परियोजनाएं संतुलित जल-वितरण की दिशा में प्रयास कर रही हैं।

जल जीवन मिशन और कमांड एरिया विकास के आधुनिकीकरण से जल की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है, जबकि नमामि गंगे जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जल गुणवत्ता सुधारने का कार्य आगे बढ़ रहा है। साथ ही, अनुसंधान, नवाचार और जन जागरूकता के माध्यम से भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने पर भी जोर दिया गया है।

इस पूरे प्रयास का मूल भाव है- जन भागीदारी। प्रधानमंत्री जी ने जलसंचय को जन आंदोलन बनाने का आहवान किया है। सरकार दिशा और संसाधन उपलब्ध करा सकती है, लेकिन स्थायी परिवर्तन तभी संभव है जब समाज स्वयं इसमें भागीदार बने।

जल जीवन मिशन इसी सोच का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना है। आज 15.8 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा पहुंच चुकी है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

इस मिशन का एक बड़ा प्रभाव महिलाओं के जीवन में दिखाई देता है। पानी लाने के श्रम में कमी आई है, स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और शिक्षा तथा आजीविका में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

ग्राम पंचायतों और स्थानीय जल एवं स्वच्छता समितियों की भूमिका से समुदाय का जुड़ाव मजबूत हुआ है, वहीं फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल गुणवत्ता की निगरानी में महिलाओं की भागीदारी ने स्थानीय स्वामित्व को और सुदृढ़ किया है।

नमामि गंगे कार्यक्रम ने गंगा और उसकी सहायक नदियों में जल गुणवत्ता सुधारने और पारिस्थितिकी तंत्र के पुर्नजीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निर्मल और अविरल गंगा के साथ-साथ अर्थ गंगा और जन गंगा जैसी पहलें नदी संरक्षण को लोगों के जीवन और आजीविका से जोड़ती हैं।

कैच द रेन अभियान और जल संचय जन भागीदारी जैसे प्रयासों ने जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों का पुर्नजवन, बोरवेल रिचार्ज और चेक-डैम निर्माण जैसे कार्यों में लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। सितंबर 2024 से अब तक देशभर में 45 लाख से अधिक वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण इसी सामूहिक प्रयास का परिणाम है। यह दिखाता है कि जब सरकार और समाज साथ मिलकर काम करते हैं, तो परिवर्तन व्यापक और स्थायी होता है।

देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे कई प्रेरक उदाहरण सामने आए हैं। गुजरात के बनासकांठा में डेयरी सहकारी समितियों और किसानों ने मिलकर कम लागत वाले रिचार्ज पिट बनाए हैं।

छत्तीसगढ़ के कोरिया में किसानों ने अपनी भूमि का एक हिस्सा भूजल पुनर्भरण के लिए समर्पित किया है। शहरी क्षेत्रों में भी आवासीय परिसर वर्षा जल संचयन और पुन: उपयोग को अपनाने लगे हैं।

उद्योग जगत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जल ऑडिट, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और वर्षा जल संचयन जैसी प्रथाओं को अपनाकर उद्योग जिम्मेदार जल प्रबंधन की दिशा में योगदान दे रहे हैं।

कृषि क्षेत्र में भी जल के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में बदलाव दिखाई दे रहा है।

माइक्रो-इरिगेशन, खेत स्तर पर बेहतर जल प्रबंधन और उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग जैसी पहलें न केवल किसानों की आय को सुदृढ़ करती हैं, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता को भी बढ़ावा देती हैं।

जल संरक्षण को जीवनशैली का हिस्सा बनाना समय की मांग है। वर्षा जल संचयन, उपचारित जल का पुन: उपयोग और पानी की बर्बादी को रोकना ऐसे कदम हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने शहरों को अधिक जल-सुरक्षित बना सकते हैं।

भारत की जल सुरक्षा की यह यात्रा एक सामूहिक राष्ट्रीय प्रयास है। यह केवल नीतियों और अवसंरचना से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और सोच में बदलाव से ही संभव है।

आइए, इस विश्व जल दिवस पर हम जल संरक्षण को अपनी आदत में लाएँ और अपने दैनिक क्रियाकलापों में शामिल करें। यदि प्रत्येक नागरिक प्रतिदिन केवल एक लीटर जल भी बचाए या उसका पुन: उपयोग करे, तो हम एक राष्ट्र के रूप में प्रतिदिन 140 करोड़ लीटर से अधिक जल बचा सकते हैं। जल संरक्षण को प्रयास नहीं, बल्कि स्वभाव बनाना होगा तभी जल सुरक्षित विकसित भारत का लक्ष्य साकार होगा।

योग 365: दैनिक जीवन में स्वास्थ्य का समावेश

इस पहल का उद्देश्य योग को दैनिक आदत बनाना है

जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) को पहली बार 2015 में विश्व स्तर पर मनाया गया, तो यह तेजी से विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य आंदोलनों में से एक बन गया। प्रति वर्ष 21 जून को, दुनिया भर के लाखों लोग पार्कों, संस्थानों और घरों में योग करते हैं।

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने बताया, 'आयुष मंत्रलय का उद्देश्य उस एक दिवसीय उत्सव की भावना को आगे बढ़ाते हुए योग को दैनिक अभ्यास में बदलना है। यह सोच 'योग 365' के रूप में साकार हुई है, जो एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका लक्ष्य योग को नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना है।'

इस पहल का औपचारिक अनावरण योग महोत्सव-2026 के शुभारंभ के दौरान किया गया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 के लिए 100 दिनों की उलटी गिनती की शुरुआत की। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) ने नि:शुल्क दैनिक ऑनलाइन योग सत्र प्रदान करने के लिए वेलनेस प्लेटफॉर्म हैबिल्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

जागरूकता से लेकर कारवाई तक

श्री जाधव ने बताया, 'भारत में पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों के बारे में जागरूकता का स्तर पहले से ही बहुत ऊंचा है, लेकिन असली चुनौती इस जागरूकता को नियमित अभ्यास में बदलने में है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के अनुसार, ग्रामीण भारत में योग जैसी पारंपरिक प्रणालियों के बारे में जागरूकता 95 प्रतिशत और शहरी भारत में 96 प्रतिशत है। एनएसएस में यह भी पाया गया कि ग्रामीण भारत में लगभग 1.1 करोड़ परिवारों और शहरी भारत में लगभग 1.4 करोड़ परिवारों में कम से कम एक सदस्य नियमित रूप से योग का अभ्यास करता है।'

श्री जाधव ने जोर देकर कहा कि जागरूकता और व्यवहार के बीच के इस अंतर को ही योग 365 अभियान पाटने का प्रयास करता है। योग मानसिक स्पष्टता, शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन के लिए एक शक्तिशाली साधना है। योग 365 के माध्यम से हमारा प्रयास लोगों को योग

को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि स्वास्थ्य एक सामयिक कार्यकलाप के बजाय जीवन शैली बन जाए।

उन्होंने कहा कि यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक उत्सव ने जागरूकता पैदा करने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन अगला चरण समुदायों, संस्थानों और कार्यस्थलों में रोजमर्रा की जिंदगी में योग को समाहित करने के बारे में है।

365 दिनों की आदत

योगा 365 के पीछे की अवधारणा सरल लेकिन महत्वाकांक्षी है जो एक दिवसीय उत्सव से आगे बढ़कर पूरे वर्ष निरंतर जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है।

इस अभियान का उद्देश्य मिशन-मोड आउटरीच के माध्यम से समुदायों को संगठित करना, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना और स्कूलों एवं कार्यालयों से लेकर पड़ोस के समूहों और डिजिटल प्लेटफार्मों तक विभिन्न स्थानों में योग को एकी त करना है।

हैबिल्ड के साथ साझेदारी इस अभियान की पहली व्यापक डिजिटल पहुंच का प्रतिनिधित्व करती है। यह प्लेटफॉर्म प्रतिदिन नि:शुल्क ऑनलाइन योग सत्र आयोजित करेगा, जिससे भौगोलिक क्षेत्रों और फिटनेस स्तर की परवाह किए बिना लोगों के लिए निर्देशित अभ्यास सुलभ हो जाएगा।

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा, 'एनएसएस के 79वें दौर के अनुसार, शहरी भारतीयों में से 96 प्रतिशत लोग हमारी चिकित्सा प्रणालियों से परिचित हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ही इनका दैनिक अभ्यास करते हैं। योग 365, गैर-संक्रामक रोगों के लिए हाल ही में शुरू किए गए योग प्रोटोकॉल के साथ मिलकर, योग को अधिक सुलभ, व्यावहारिक और रोजमर्रा के स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक बनाकर इस अंतर को पाटने का प्रयास करता है।'

एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य अभियान

डिजिटल सत्रों के अलावा, योग 365 एक व्यापक अभियान के रूप में काम करेगा जो आयुष मंत्रालय की योग से संबंधित कई पहलों को आपस में जोड़ेगा। इस कार्यनीति में दैनिक अभ्यास के अवसरों को बढ़ाने के लिए संस्थानों, कॉर्पोरेट संगठनों, सामुदायिक समूहों और शैक्षिक नेटवर्को के साथ सहयोग शामिल है।

अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान व्यापक स्तर पर नागरिक सहभागिता, व्यवहार परिवर्तन संचार और संस्थागत एकीकरण पर केंद्रित होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि योग रोजमर्रा की दिनचर्या का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाए।

आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मोनालिसा डैश ने जोर देते हुए कहा, 'योग 365 पूरे देश में दैनिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की संस्कृति को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। सामुदायिक भागीदारी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और संस्थागत सहभागिता को मिलाकर, इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योग हर घर तक पहुंचे और एक स्थायी जीवनशैली का हिस्सा बन जाए।'

योग 365: रोजमर्रा की जिंदगी में सेहत को अपनाएं

योगा 365 का उद्देश्य केवल पूरे वर्ष योग का अभ्यास करना ही नहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गो के दैनिक जीवन में स्वास्थ्य को एकीकृत करना भी है। कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए वाई-ब्रेक, आम जनता के लिए क मन योगा प्रोटोकॉल (सीवाईपी) और रोग प्रबंधन के लिए चिकित्सीय योग प्रोटोकॉल जैसी पहलें दर्शाती हैं कि योग कार्यस्थल पर स्वास्थ्य, दैनिक फिटनेस और निवारक स्वास्थ्य देखभाल में कैसे सहायक हो सकता है। ये सभी प्रयास मिलकर योग को दैनिक जीवन में स्वास्थ्य और संतुलन सुधारने का एक व्यावहारिक साधन बनाने के व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं।

21 जून से आगे बाद

जैसे-जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 निकट आ रहा है, योग 365 भारत के योग आंदोलन के अगले चरण का संकेत देता है-एक ऐसा चरण जो सार्वजनिक कार्यक्रमों और जनसभाओं से परे है।

पिछले एक दशक में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक प्रतीकात्मक आयोजन से विकसित होकर एक शक्तिशाली वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन बन गया है। 2015 में समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के सामूहिक प्रयास के रूप में शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे-धीरे दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवनशैली पहलों में से एक बन गया है। वर्ष 2025 में योग दिवस के अवसर पर 26 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी इस आंदोलन की बढ़ती पहुंच और गति को और भी स्पष्ट करती है। इससे यह पता चलता है कि योग किस प्रकार स्वास्थ्य, सद्भाव और सामूहिक कल्याण के लिए एक वैश्विक शक्ति के रूप में विकसित हुआ है।

यह विजन सरल लेकिन परिवर्तनकारी है: यदि लाखों लोग एक दिन के लिए योग करते हैं, तो वे इसका अभ्यास प्रतिदिन भी कर सकते हैं।

देश भर में पहले से ही विद्यमान जागरूकता को देखते हुए, योग 365 की सफलता संभवत: उस जागरूकता को एक सरल दैनिक आदत में बदलने की उसकी क्षमता में निहित है-एक ऐसी आदत जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सामूहिक कल्याण दोनों को सुदृढ़ करती है।

हर घर शुद्ध पेयजल और हर खेत तक सिंचाई सरकार की प्राथमिकता:मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल और हर खेत तक सिंचाई योग्य पानी पहुंचाना है। इस दिशा में जल शक्ति विभाग निरंतर कार्य कर रहा है।

उप-मुख्यमंत्री बद्दी में विश्व जल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय जल महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की 24X7 सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका अहम है।

इस अवसर पर उन्होंने दून और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में टयूबवेल स्थापना व सुदृढ़ीकरण के लिए 2-2 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। यह राशि जल शक्ति विभाग और बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही दोनों क्षेत्रों में विभाग के 50-50 अतिरिक्त पद भरने का आश्वासन भी दिया गया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग द्वारा लगभग 10 हजार योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत करीब 6 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि विभिन्न योजनाओं के एवज में 1227 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के पास लंबित हैं।

उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रें में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये की नई योजना तैयार की जा रही है। इसके अलावा भू-जल रिचार्ज, पुरानी योजनाओं के पुनरुद्धार और जल स्रोतों के संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहां प्रतिदिन लगभग 16 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। वर्तमान में बद्दी-नालागढ़ क्षेत्र में करीब 500 टयूबवेल स्थापित किए जा चुके हैं।

कार्यक्रम के दौरान उप-मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मियों के मौसम में जलापूर्ति के लिए समुचित तैयारी रखें और आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर जल वितरण को मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क जल उपलब्ध कराने की नीति का भी उल्लेख किया।

इस अवसर पर जल शक्ति विभाग की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया तथा जल प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को 'नीर नारी सम्मान' और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में दून के विधायक राम कुमार चौधरी, नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कांगड़ा के विधायकों ने ग्रामीण हितों पर केंद्रित बजट के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार

शिमला/शैल। कांगड़ा जिले के कांग्रेस विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट कर वर्ष 2026-27 के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रावधानों के लिए आभार व्यक्त किया।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों को गांवों, गरीबों और किसानों के कल्याण की दिशा में प्राथमिकता दी है। उनके अनुसार, दूध के खरीद मूल्य में वृद्धि से पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। बजट में गाय के दूध का मूल्य 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का 71 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही, दूध को संग्रहण केंद्र तक पहुंचाने के लिए परिवहन सहायता राशि 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।

विधायकों ने भेड़ पालकों के लिए ऊन पर 100 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाने को भी महत्वपूर्ण कदम बताया। इसके अलावा, प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं और जौ का MSP 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्का का 50 रुपये प्रति किलोग्राम और हल्दी का 150 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। अदरक को पहली बार MSP के दायरे में शामिल करते हुए इसका मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बताया कि कांगड़ा जिले के ढगवार में लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, नाहन और नालागढ़ में भी करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से ऐसे संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रखे जाएंगे।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया सहित विधायक किशोरी लाल, आशीष बुटेल, संजय रत्तन, मलेंदर राजन, कमलेश ठाकुर और संजय अवस्थी उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री ने नालागढ़ में 25 करोड़ की परियोजनाएं शुरू कीं

शिमला। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में करीब 25 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत कश्मीरपुर के मलपुर में 13.36 करोड़ रुपये की लागत से 11 नलकूप आधारित सिंचाई योजनाओं की आधारशिला रखी गई, जिनसे 9 पंचायतों के 11 गांवों को लाभ मिलेगा।

इससे पूर्व उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बद्दी स्थित नालागढ़ कार्यालय एवं आवासीय परिसर का भी शिलान्यास किया। इस परिसर के निर्माण पर 11.24 करोड़ रुपए व्यय होंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दी जा रही है और सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि जल शक्ति मंडल नालागढ़ के तहत 120 पेयजल और 170 सिंचाई परियोजनाएं संचालित हैं, जिनसे 758 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल संरक्षण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

इस अवसर पर नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।

शून्य सहनशीलता नीति के साथ नशे के खिलाफ सख्त कारवाई 4 पुलिसकर्मी बर्खास्त

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 'चिट्टा-मुक्त हिमाचल' अभियान के तहत नशीले पदार्थों के खिलाफ कारवाई तेज कर दी है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू द्वारा 15 नवंबर 2025 को शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें आम जनता की भागीदारी भी बढ़ रही है।

पुलिस ने बताया कि राज्यभर में समन्वित और सघन अभियान चलाकर चिट्टा सहित अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कारवाई की जा रही है। 'शून्य सहनशीलता' नीति के तहत विभाग के भीतर भी सख्त कदम उठाए गए हैं।

इसी क्रम में एसटीएफ कुल्लू के चार पुलिस कर्मियों कांस्टेबल नितेश, कांस्टेबल अशोक, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार और हेड कांस्टेबल समीर कुमार को एनडीपीएस मामलों में संलिप्त पाये जाने पर सेवा से बर्खास्त किया गया है। इससे पहले भी 17 पुलिस कर्मियों को नशा संबंधित मामलों में हटाया जा चुका है, जिससे कुल संख्या 21 हो गई है।

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि नशा तस्करी में किसी भी पुलिस कर्मी की संलिप्तता पाये जाने पर कड़ी कारवाई की जाएगी। साथ ही, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी सख्ती की जाएगी।

पुलिस ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि नशे से संबंधित किसी भी जानकारी को तुरंत आपातकालीन नंबर 112 या नजदीकी थाने में साझा करें।

वित्तीय चुनौतियों के बावजूद जनकल्याण और विकास पर केंद्रित बजट

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की सराहना करते हुए इसे दूरदर्शी, सशक्त और ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत आधारशिला साबित होगा।

मंत्रियों ने कहा कि गंभीर वित्तीय चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री ने जनकल्याण, समावेशी विकास और प्रशासनिक दक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूती से दर्शाया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान में कटौती से राज्य को लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद संतुलित और प्रगतिशील बजट प्रस्तुत किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. शांडिल ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3,000 करोड़ रुपये के प्रावधान को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों और स्टाफ नर्सों के हजारों पद भरने के निर्णय का स्वागत किया। साथ ही, सीनियर रेजिडेंट स्पेशलिस्ट और सुपर-स्पेशलिस्ट के स्टाइपेंड में वृद्धि को राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने और मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ करने से दूरदराज क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचेंगी। कुपोषण, एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए स्टेट न्यूट्रीशन पॉलिसी को पोषण अभियान के अनुरूप लाना भी सराहनीय पहल है।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राजस्व विभाग में डिजिटल परिवर्तन की पहल को आम जनता के लिए राहतकारी बताया। उन्होंने कहा कि भूमि अभिलेखों और म्यूटेशन प्रक्रियाओं के सरलीकरण से पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक बाधाएं समाप्त होंगी। राजस्व चौकीदारों के मानदेय को बढ़ाकर 6,800 रुपये किए जाने के निर्णय का भी उन्होंने स्वागत किया।

मंत्रियों ने युवाओं के सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर विशेष जोर देने की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि बजट के माध्यम से पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भर्तियों का मार्ग प्रशस्त होगा और रोजगार योजनाओं के तहत 4 लाख मानव-दिवस सृजित किए जाएंगे।

मंत्रियों ने कहा कि वित्तीय दबावों के बावजूद मुख्यमंत्री की सादगी और प्रतिबद्धता प्रदेश के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट 'आत्मनिर्भर हिमाचल' के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा।

बजट आम जनता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित:नरदेव कंवर

शिमला/शैल। नरदेव सिंह कंवर ने वर्ष 2026-27 के बजट को आम जनता और ग्रामीण हितों पर केंद्रित बताते हुए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की सराहना की है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले मुख्यमंत्री ने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद साहसिक निर्णय लेते हुए ऐसा बजट पेश किया है, जो प्रदेश में वित्तीय अनुशासन के साथ सतत विकास को भी गति देगा।

कंवर के अनुसार बजट में किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए दुग्ध, हल्दी, गेहूं, मक्की सहित विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है और अदरक के लिए पहली बार समर्थन मूल्य तय किया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सामाजिक कल्याण के तहत एक लाख जरूरतमंद परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और बीपीएल परिवारों की महिलाओं को 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना' के तहत 1500 रुपये मासिक सहायता प्रदान करने की घोषणा सराहनीय है।

अध्यक्ष ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मचारियों के वेतन तथा आउटसोर्स व परियोजना कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि कर सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह आर्थिक तंगी के बावजूद हर वर्ग के साथ खड़ी है। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रें पर विशेष ध्यान देने से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

उन्होंने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा छः माह तक वेतन में अस्थायी कटौती के निर्णय को जनहित में बताया और कहा कि इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी।

वित्तीय संकट, कर्ज और कर्मचारियों पर बोझ का प्रतीक बजट:विपिन परमार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक विपिन परमार ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बजट को 'आर्थिक कुप्रबंधन का दस्तावेज' करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में कटौती, कर्मचारियों के वेतन स्थगन और बढ़ते कर्ज का बोझ राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति को उजागर करता है।

परमार ने कहा कि इस बार का कुल बजट 54,928 करोड़ रूपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष के 58,514 करोड़ रूपये से 3,586 करोड़ रूपये कम है। उनके अनुसार, बजट में यह कमी इस बात का संकेत है कि सरकार विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने दावा किया कि संसाधनों की कमी और बढ़ते वित्तीय दबाव के कारण सरकार अब खर्चों में कटौती करने को मजबूर है, जिसका सीधा असर विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं पर पड़ेगा।

सबसे बड़ा मुद्दा कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा है। परमार ने आरोप लगाया कि सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन का हिस्सा छः महीनों के लिए स्थगित कर दिया है। इसके अलावा ग्रुप-ए और ग्रुप-बी अधिकारियों के वेतन का 3 प्रतिशत हिस्सा भी रोका गया है।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन, भत्ते और पेंशन देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन वर्तमान स्थिति में सरकार उनसे ही 'बलिदान' मांग रही है। परमार के अनुसार, यह न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित करेगा बल्कि कर्मचारियों में असंतोष भी बढ़ाएगा, जिसका असर सरकारी कामकाज पर पड़ सकता है।

आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने न्यूनतम वेतन 13,750 रूपये प्रतिमाह तय किया है, लेकिन यह राशि मौजूदा महंगाई के दौर में अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि यह वर्ग लंबे समय से शोषण का शिकार है, लेकिन बजट में उनके लिए कोई ठोस नीति नहीं लायी गयी।

परमार ने यह भी कहा कि सरकार एक ओर वेतन स्थगित कर रही है, वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और अन्य वर्गों के मानदेय में 500 से 1000 रूपये तक की वृद्धि कर 'दिखावटी राहत' देने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार खुद स्वीकार कर चुकी है कि उस पर लगभग 13,000 करोड़ रूपये की देनदारियां हैं, जबकि कुल कर्ज 45,000 करोड़ रूपये से अधिक हो चुका है। ऐसे में कर्ज लेकर कर्ज चुकाने की नीति राज्य को और गहरे वित्तीय संकट में धकेल सकती है। उन्होंने इसे 'अस्थायी समाधान' बताते हुए कहा कि इससे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित नहीं हो सकती।

भाजपा नेता ने सरकार से कई सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि क्या कर्मचारियों का वेतन स्थगित करना ही वित्तीय सुधार का रास्ता है? क्या आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देकर उनका भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है? और क्या सरकार अपनी आर्थिक नीतियों की विफलता स्वीकार करेगी?

उन्होंने मांग की कि वेतन स्थगन का फैसला तुरंत वापस लिया जाए और कर्मचारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाये। साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी और स्पष्ट नीति बनाई जाये, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

परमार ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए, तो इसका राजनीतिक और प्रशासनिक असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा।

हिमाचल में ईपीएफओ के 24.68 लाख सदस्य, दावे औसतन 8 दिन में निपट रहे

शिमला/शैल। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत हिमाचल प्रदेश में 24,68,515 पंजीकृत सदस्य हैं, जबकि 5,14,741 अंशदाई सदस्य हैं। यह जानकारी उन्होंने राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी के प्रश्न के उत्तर में दी।

मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रोविडेंट फंड से जुड़े दावों का निपटारा औसतन आठ दिनों के भीतर किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिल रही है।

जिलावार आंकड़ों के अनुसार, सोलन जिले में सबसे अधिक 16,20,735 पंजीकृत और 3,05,333 अंशदाई सदस्य हैं। इसके अलावा सिरमौर में 2,60,740 पंजीकृत और 63,316 अंशदाई सदस्य, शिमला में 1,67,807 पंजीकृत और 45,555 अंशदाई सदस्य तथा ऊना में 1,13,972 पंजीकृत और 23,006 अंशदाई सदस्य दर्ज किए गए हैं।

अन्य जिलों में भी हजारों सदस्य ईपीएफओ से जुड़े हैं, जिनमें कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, कुल्लू और हमीरपुर प्रमुख हैं। लाहौल-स्पीति जैसे दूरदराज क्षेत्रों में भी सदस्यता दर्ज की गई है, हालांकि वहां संख्या अपेक्षाकृत कम है।

मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ में डिजिटल प्रणाली अपनाने से पारदर्शिता, दक्षता और सेवा गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इससे प्रक्रियाएं तेज हुई हैं और कागजी कार्यवाही में कमी आई है, जिसके चलते दावों के त्वरित निपटारे और सामाजिक सुरक्षा खातों के प्रभावी संचालन में सहायता मिली है।

एनएचएम के तहत हिमाचल को 504.29 करोड़

शिमला/शैल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप जाधव ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश को 504.29 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह जानकारी राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी के प्रश्न के उत्तर में दी।

मंत्री ने बताया कि इसी अवधि के लिए अन्य राज्यों को भी एनएचएम के तहत अलग-अलग राशि जारी की गई है। पंजाब को 572.66 करोड़, हरियाणा को 480.71 करोड़, राजस्थान को 1,953.77 करोड़, दिल्ली को 254.54 करोड़, उत्तराखंड को 563.15 करोड़, जम्मू-कश्मीर को 669.32 करोड़ और लद्दाख को 141.86 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि देश में सबसे अधिक राशि उत्तर प्रदेश को 5,027.46 करोड़ रुपये जारी की गई है, जबकि सबसे कम 10.55 करोड़ रुपये लक्षद्वीप को मिले हैं।

मंत्री के अनुसार, यह धनराशि राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जारी की जाती है।

42 किमी सड़क के सुधार व चौड़ीकरण की केन्द्र से मांग:कश्यप

शिमला/शैल। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने लोकसभा में नियम 377 के तहत जिला सिरमौर के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़े सराहां-चंडीगढ़ मार्ग की जर्जर स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए इस 42 किलोमीटर लंबे मार्ग के शीघ्र सुधार और चौड़ीकरण की मांग की।

सांसद कश्यप ने कहा कि यह मार्ग क्षेत्र की छः ग्राम पंचायतों को जोड़ने के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश को हरियाणा और चंडीगढ़ से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण अंतर-राज्यीय संपर्क मार्ग है। वर्तमान में सड़क की स्थिति अत्यंत खराब है और हाल ही में हुई भारी वर्षा व भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर मार्ग को गंभीर नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने बताया कि सड़क संकरी, टूटी हुई और जोखिमपूर्ण हो चुकी है, जिससे प्रतिदिन आवागमन करने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खराब सड़क के चलते स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रभावित हो रही है, जबकि किसानों को अपनी उपज समय पर बाजार तक पहुंचाने में कठिनाई हो रही है।

सांसद ने सरकार से आग्रह किया कि इस मार्ग के सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और स्थायी समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सड़क क्षेत्र की 'जीवनरेखा' है और इसके सुधार में देरी जनहित के साथ अन्याय होगा।

पीएम-श्री योजना के तहत हिमाचल के 199 स्कूल आधुनिक सुविधाओं से होंगे लैस

शिमला/शैल। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि पीएम-श्री स्कूल योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के 199 स्कूलों का चयन किया गया है। यह जानकारी उन्होंने राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी के प्रश्न के उत्तर में दी।

मंत्री ने बताया कि इन स्कूलों में केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, इंटरनेट सुविधाएं और आधुनिक खेल अवसंरचना विकसित की जा रही है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिल सके।

जिलावार जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बिलासपुर में 9, चंबा में 16, हमीरपुर में 17, कांगड़ा में 30, किन्नौर में 3, कुल्लू में 15, लाहौल-स्पीति में 2, मंडी में 30, शिमला में 24, सिरमौर में 15, सोलन में 21 और ऊना में 17 पीएम-श्री स्कूल कार्यरत हैं।

मंत्री ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देशभर में 14,500 स्कूलों को पीएम-श्री योजना के तहत विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 13,091 स्कूलों का चयन किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से स्कूलों को आधुनिक और समग्र शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और भविष्य उन्मुख शिक्षा मिल सके।

गगरेट में आधुनिक मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र को मंजूरी

3615 पंचायतों को भारतनेट-III से जोड़ा जाएगा

शिमला/शैल। भाजपा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने लोकसभा में हिमाचल प्रदेश से जुड़े मुद्दे उठाते हुए केंद्र सरकार से जानकारी प्राप्त की है। इसमें मत्स्य पालन और डिजिटल कनेक्टिविटी से संबंधित दो प्रमुख घोषणाएं सामने आयी हैं।

केंद्र सरकार ने ऊना जिले के गगरेट में अत्याधुनिक मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बताया गया है कि यह केंद्र मत्स्य पालन क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और नवाचार को बढ़ावा देने में सहायक होगा, जिससे स्थानीय मछुआरों और मत्स्य कृषकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

सांसद ने यह भी बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा का दायरा बढ़ाकर मछुआरों तक किया गया है, जिससे उन्हें कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना और आजीविका को सुदृढ़ करना है।

इसके अलावा, भारतनेट परियोजना-III के तहत कांगड़ा और चंबा जिलों सहित प्रदेश की 3615 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बीएसएनएल को नामित किया गया है, जबकि आईटीआई लिमिटेड को कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 20 एमबीपीएस तक की इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की संभावना जताई गई है।

सांसद ने कहा कि ये पहलें प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में सहायक होंगी।

हमीरपुर-मरांडा सड़क परियोजना को मंजूरी

शिमला/शैल। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हमीरपुर सुजानपुर थुरल मरांडा सड़क मार्ग को सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत विकसित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। यह जानकारी राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने दी।

सांसद के अनुसार, यह सड़क हमीरपुर और कांगड़ा जिलों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है, जिससे लगभग पांच लाख लोगों को बेहतर और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत सभी पुलों को डबल लेन किया जाएगा और पालमपुर-सुजानपुर-हमीरपुर मार्ग की संकरी सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा।

परियोजना पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके पूरा होने से हमीरपुर और पालमपुर के बीच दूरी कम होगी तथा पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक बजट प्रावधान सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के अन्य प्रमुख मार्गों के विकास के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास को मजबूती मिल सके।

हिमाचल बजट निराशाजनक और जन-विरोधी: इंदु गोस्वामी

शिमला/शैल। इंदु गोस्वामी ने हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2026-27 के बजट को निराशाजनक और जन-विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता और जनहित की अनदेखी करता है।

गोस्वामी ने आरोप लगाया कि सरकार पर्यटन विकास के दावे तो करती है, लेकिन बजट में पर्यटन और परिवहन क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। इससे पर्यटन उद्योग से जुड़े कारोबारियों और पेशेवरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि खुद को जनहितैषी बताने वाली हिमाचल प्रदेश की सरकार सामाजिक सेवाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान करने में विफल रही है। इसके चलते वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन के समय पर भुगतान पर असर पड़ सकता है, जिससे समाज के कमजोर वर्ग प्रभावित होंगे।

सांसद ने सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए किए गए बजट प्रावधानों को अपर्याप्त बताते हुए इसे ''ऊंट के मुंह में जीरा'' करार दिया। उन्होंने कहा कि एक ग्रामीण प्रधान राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करती है।

गोस्वामी ने कहा कि बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन के ठोस उपायों का अभाव है। साथ ही, राजनेताओं और अधिकारियों के वेतन में अस्थायी कटौती को उन्होंने ''आंखों में धूल झोंकने'' जैसा कदम बताया।

उन्होंने सरकार से फिजूलखर्ची पर रोक लगाने, भ्रष्टाचार पर सख्ती से लगाम कसने और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने की मांग की, ताकि व्यापक जनहित में प्रभावी कार्य किए जा सकें।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

बजट घोषणाओं पर भाजपा सांसदों ने सरकार को घेरा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गये 54,928 करोड़ रूपये के बजट ने राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। विपक्ष ने इस बजट को राज्य की बिगड़ती वित्तीय सेहत का प्रमाण बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाये हैं। बजट के घटे आकार से लेकर वेतन स्थगन, अधूरी गारंटियों और जमीनी स्तर पर न पहुंचने वाली योजनाओं तक भाजपा सांसदों ने सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश की है।

सबसे कड़ी प्रतिक्रिया राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन की ओर से आई, जिन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के 58,514 करोड़ रूपये की तुलना में इस बार का बजट 54,928 करोड़ रूपये रह जाना स्पष्ट संकेत है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। उन्होंने इसे कांग्रेस सरकार की 'वित्तीय विफलता' का सीधा सबूत बताया। महाजन ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए कर्मचारियों का वेतन तक स्थगित करने को मजबूर हुई है, जबकि दूसरी ओर छोटे मानदेय बढ़ाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। उनके शब्दों में, 'यह बजट विकास का नहीं, बल्कि वित्तीय दिवालियापन का दस्तावेज है।'

उधर, राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने सरकार की गारंटियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में 100% गारंटी पूरी करने का दावा दोहराया गया, लेकिन पिछले तीन वर्षों में एक भी प्रमुख गारंटी जमीन पर नहीं उतरी। सिकंदर कुमार का कहना है कि कर्मचारियों के वेतन का 3% से लेकर 50% तक स्थगित करना इस बात का प्रमाण है कि राजकोषीय स्थिति बेहद विकट है। उन्होंने कहा, 'जब सरकार खुद वेतन नहीं दे पा रही, तो वह विकास के वादे कैसे पूरा करेगी?'

लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप ने बजट को 'किसान, जवान और गरीब – सभी को धोखा देने वाला' करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार दूध और फसलों के एमएसपी बढ़ाने की घोषणा जरूर कर रही है, लेकिन किसानों को न तो बाजार में उचित मूल्य मिल रहा है और न ही वास्तविक भुगतान मिल रहा है। कश्यप ने गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा को भी 'चुनावी जुमला' बताया। उनका तंज था, 'घोषणाओं की खेती हो रही है, लेकिन किसानों के खेत सूखे पड़े हैं।'

वित्तीय अनुशासन और भविष्य की योजना पर भी विपक्ष ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में न तो कोई ठोस आर्थिक रोडमैप है और न ही उन कदमों का जिक्र, जिनसे राजस्व बढ़ाया जा सके। ठाकुर ने कटाक्ष करते हुए कहा, 'यह बजट नहीं, कांग्रेस का 'मैनेजमेंट ऑफ फेल्योर' है।' उन्होंने यह भी कहा कि वेतन स्थगन जैसे कदम बताता है कि सरकार पूरी तरह से वित्तीय संकट में फंस चुकी है, जबकि जनता को भ्रमित करने के लिए प्रचार आधारित योजनाएं लाई जा रही हैं।

इसी कड़ी में लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि सरकार खर्च की प्राथमिकताओं को तय करने में असफल रही है। भारद्वाज के अनुसार, वेतन रोकने और योजनाओं की नई घोषणाओं का कोई संतुलन दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि सरकार जनता से बलिदान की अपेक्षा तो कर रही है, लेकिन खुद जवाबदेही से बच रही है। 'वेतन स्थगन और योजनाओं की भरमार – नीति कहीं नहीं, केवल दिखावा,' उन्होंने तीखा टिप्पणी करते हुए कहा।

महिलाओं और युवाओं से जुड़े वादों पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा है। लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने महिला सम्मान राशि के वादे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 1500 रूपये प्रतिमाह देने की घोषणा तीन वर्षों से सिर्फ कागजों में है और अब फिर से उसी वादे को बजट में दोहराया जा रहा है। कंगना रनौत ने युवाओं के लिए रोजगार योजनाओं को 'खोखला' बताते हुए कहा कि सरकार नौकरी देने के बजाये उन्हें केवल प्रशिक्षण और भत्तों के नाम पर बहला रही है। उन्होंने कहा, 'यह बजट उम्मीद का नहीं, निराशा और धोखे का प्रतीक है।'

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हिमाचल की आर्थिक चुनौतियां वास्तविक हैं – राजस्व में कमी, केंद्र से मिलने वाले अनुदानों में कटौती और बढ़ते वेतन – पेंशन भार ने सरकार के लिए कठिन परिस्थितियां खड़ी की हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई ठोस समाधान प्रस्तुत करने में विफल रही है। बजट में कई नई घोषणाएं की गई हैं, पर विपक्ष का कहना है कि पिछले वादे ही पूरे नहीं हुए, तो नई घोषणाओं पर भरोसा कैसे किया जाए?

बजट पर इस तीखी राजनीतिक जंग के बीच अब आम जनता की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार जमीनी स्तर पर राहत दे पाएगी या विपक्ष के आरोप आने वाले महीनों में और अधिक तेज होंगे। फिलहाल, विपक्ष ने साफ संकेत दे दिया है कि वे बजट को लेकर सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के लिए तैयार हैं, जबकि सरकार इस बजट को विकासोन्मुखी और संतुलित बताने में जुटी है।

आंकड़ों के सहारे सरकार पर हमलावर जयराम

विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर उजागर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट 2026 – 27 पर चर्चा के दौरान सियासी टकराव तेज हो गया, जब पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के बजट को 'प्रदेश को गुमराह करने वाला झूठ का पुलिंदा' करार दिया।

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार ने अधिकांश योजनाओं की घोषणाएं बिना पर्याप्त बजट प्रावधान के की हैं और पिछले तीन वर्षों में घोषित कई योजनाएं जमीन पर उतर ही नहीं पायी। उन्होंने कहा कि बजट का आकार स्थिर रहना और प्रमुख क्षेत्रों में लगातार कटौती विकास की दिशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उनके अनुसार, 2024 – 25 की तुलना में पिछले वर्ष मेजर सेक्टर में 2354 करोड़ (21%) की कमी आई, जबकि आगामी वित्त वर्ष में यह कटौती 3188 करोड़ (41.77%) तक पहुंच गई है। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि और सड़क जैसे क्षेत्रों में कटौती को उन्होंने 'आत्मनिर्भर हिमाचल' के दावों के विपरीत बताया।

उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय तीन वर्षों में घटकर लगभग आधा रह गया है, जबकि राजस्व घाटा लगातार बढ़ रहा है। पिछले चार बजटों में औसतन 10,620 करोड़ रुपये का घाटा वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़ा करता है। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के दौरान सरकारी नौकरियों में वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगभग 15 हजार नौकरियां कम हो गई हैं। उनके मुताबिक, 2022 में जहां सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1.90 लाख के करीब थी, वहीं 2025 में यह घटकर 1.75 लाख रह गई है।

केंद्र – राज्य संबंधों को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगाती है, जबकि वास्तविकता यह है कि राजस्व प्राप्तियों में केंद्र की हिस्सेदारी पिछले तीन वर्षों में 56%, 54% और 53.6% रही है। केंद्रीय करों, अनुदानों और योजनाओं के माध्यम से राज्य को निरंतर वित्तीय सहयोग मिलता रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि खेत बाड़ाबंदी योजना का बजट 40 करोड़ से घटाकर 10 करोड़ कर दिया गया है, जबकि बिजली सब्सिडी 1562 करोड़ से घटकर 858 करोड़ रह गई है। हिमकेयर जैसी योजनाओं में भी कटौती के संकेत बताये गये। उन्होंने वेतन प्रावधानों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 2026 – 27 के बजट में वेतन के लिए 14,721 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो पिछले वर्ष से मात्र 5 करोड़ अधिक है, जिससे महंगाई भत्ता देने की मंशा पर संदेह होता है। साथ ही, वेतन स्थगन के संकेतों को उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध बताया।

जयराम ठाकुर ने बजट भाषण और दस्तावेजों के आंकड़ों में अंतर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जहां बिजली रॉयल्टी 2,500 करोड़ बताई गई, वहीं बजट में प्राप्ति 2,191 करोड़ दिखाई गई है, जो दावों और वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर को दर्शाता है। इसी तरह आबकारी राजस्व अनुमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।

उन्होंने अंत में सवाल उठाया कि जब बजट के आंकड़े ही सरकार के दावों का समर्थन नहीं कर रहे, तो विकास के दावे कितने विश्वसनीय हैं। वहीं, सरकार की ओर से बजट को संसाधन – आधारित और संतुलित बताते हुए इन आरोपों को खारिज किया जा रहा है।